



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 43]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 31, 2005/चैत्र 10, 1927

No. 43]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 31, 2005/CHAITRA 10, 1927

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 28 मार्च, 2005

सं. टीएएमपी/26/2003-टीपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा अपने वर्तमान दरमान की वैधता के विस्तार के लिए तृतीकोरिन पत्तन न्यास से प्राप्त प्रस्ताव को इसके साथ संलग्न आदेश के अनुसार, निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/26/2003-जेएनपीटी

तृतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी)

आवेदक

आदेश

(मार्च 2005 के 15वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने तृतीकोरिन पत्तन न्यास (टीपीटी) के दरमान के सामान्य संशोधन को स्वीकृति प्रदान करते हुए 20 सितम्बर, 2002 को एक आदेश पारित किया था। संशोधित दरमान के साथ वह आदेश भारत के राजपत्र में 4 अक्टूबर, 2002 को राजपत्र सं. 224 के माध्यम से अधिसूचित किया गया था।

1.2 उक्त आदेश में लागत विवरणियों द्वारा प्रतिबिम्बित अतिशेष स्थिति को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से अनुमोदित मदों को छोड़कर इस प्राधिकरण ने टीपीटी द्वारा दरों वृद्धि वाले संशोधन को अस्वीकार कर दिया था और टीपीटी को परामर्श दिया था कि वह अपने उपयोगकर्ताओं की सलाह से प्रशुल्क में कमी के लिए उपयुक्त प्रस्ताव लेकर आए।

2.1 इस प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन में 5.31% का औसत घाटा दर्शाते हुए, पहले वर्ष 2002-03 और 2003-04 की संशोधित लागत विवरणियां दाखिल की थीं और यह उल्लेख किया कि (दरों में) कमी करने वाले संशोधन की वहां कोई गुंजाइश नहीं थी, बल्कि प्रशुल्क में बढ़ोत्तरी करने वाले संशोधन की गुंजाइश थी। उसके बावजूद, टीपीटी ने इस प्राधिकरण से, अन्य भारतीय पत्तनों के प्रशुल्क की तुलना में इसे स्पर्धात्मक बनाए रखने के लिए, अपने पिछले आदेश में अनुमोदित दरों पर प्रशुल्क को जारी रखने का अनुरोध किया था।

2.2 टीपीटी द्वारा दिसम्बर, 2003 में दाखिल की गई लागत विवरणियों की जांच पड़ताल की गई ताकि इस प्राधिकरण के दिनांक 20 सितम्बर, 2002 के आदेश के साथ संलग्न लागत विवरणियों के संदर्भ से, टीपीटी द्वारा दिसम्बर, 2003 में दाखिल लागत विवरणियों में से मेल न खाने वाली बातों को बाहर निकाला जा सके। हमारे द्वारा परिवर्तित लागत विवरणियों ने लगभग उसी स्तर पर निम्बल अतिशेष स्थिति दर्शाई जो पिछले सामान्य संशोधन के समय पाई गई थी। तथापि, जैसाकि अगला सामान्य संशोधन सितम्बर, 2004 में अपेक्षित था, इस प्राधिकरण ने तात्कालिक प्रशुल्क स्तर को एक और वर्ष अर्थात् सितम्बर, 2004 तक विस्तार प्रदान करने का टीपीटी का अनुरोध इस निदेश के साथ मान लिया कि वह सामान्य समीक्षा के लिए अपना व्यापक प्रस्ताव 30 जून, 2004 तक प्रस्तुत कर देगा। टीपीटी को यह भी सलाह दी गई थी कि वह, उसे पहले से प्रदत्त लचीलेपन का उपयोग करे और लागत विवरणी में प्रतिबिम्बित निम्बल अतिशेष की सीमा तक कार्गो और पोत संबंधी प्रभारों में कमी करे।

3.1 इस प्राधिकरण के निर्णय के संदर्भ से, टीपीटी ने वर्ष 2003-04 के वास्तविक के आधार पर लागत विवरणी प्रस्तुत की और वर्ष 2004-05 के लिए संशोधित अनुमान प्रस्तुत किए। टीपीटी द्वारा दाखिल लागत विवरणी वर्ष 2003-04 और 2004-05 के लिए 5.16% का औसत घाटा दिखाती है।

3.2 टीपीटी ने बताया है कि वर्ष 2001-02 में यातायात 130.17 लाख टन से वर्ष 2004-05 में 141.99 लाख टन हो जाने के बावजूद वह पूंजीगत परियोजनाओं में बढ़ते व्यय बकाया जापानी ऋण और भीतरी हार्बर के इष्टतम उपयोग हेतु अन्य पूंजीगत व्यय प्रस्ताव की आवश्यकता पूरी करने, विद्युत प्रणाली को अपग्रेड करने इत्यादि के लिए पर्याप्त संसाधन उत्पन्न नहीं कर पाया। पड़ोसी पत्तनों से स्पर्धा के चलते बंदरगाह भाड़ा दरों और विभिन्न प्रशुल्क मदों में विभिन्न प्रोत्साहन/छूट योजनाएं लागू की गई हैं जिससे प्रचालनीय आय घटने की संभावना है। पोत परिवहन मंत्रालय (तत्कालीन) से प्राप्त, निदेशों के अनुपालन में, मुख्य मार्ग कन्टेनर पोतों के मामले में, पोत संबंधी प्रभारों में 65% रियायत प्रस्तुत की गई है। इससे प्रचालनीय आय में लगभग 5.17 करोड़ रुपये प्रति वर्ष की कमी आने की संभावना है।

3.3 इस परिप्रेक्ष्य में, और लागत विवरणी द्वारा प्रतिबिम्बित घाटे की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, टीपीटी ने अपने वर्तमान की दरमान वैधता 30 सितम्बर, 2005 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है। टीपीटी ने अगली समीक्षा के लिए अपना प्रस्ताव 30 जून, 2005 तक प्रस्तुत करना स्वीकार कर लिया है।

4.1 टीपीटी द्वारा प्रस्तुत की गई लागत विवरणी की टीपीटी के दरमान की पिछली सामान्य समीक्षा के समय अनुसरण किए गए दृष्टिकोण के अनुरूप और अन्य महापत्तनों के प्रशुल्क संशोधन/समीक्षा प्रक्रिया में इस प्राधिकरण द्वारा समान रूप से अनुपालित सामान्य सिद्धांत के संदर्भ से उसमें पाई गई कुछ विसंगतियां दूर कर ली गई हैं।

4.2 समग्र पत्तन के लिए हमारे द्वारा तैयार की गई लागत विवरणी टीपीटी द्वारा बताए गए 5.16% औसत निम्बल घाटे की तुलना में वर्ष 2003-04 और 2004-05 के लिए प्रचालनीय आय का 6.77% औसत निम्बल अतिशेष दिखाती है। प्रशुल्क में प्रस्तुत की गई विभिन्न रियायतों के संदर्भ से यदि आय अनुमानों को अद्यतन किया गया तो लागत विवरणी द्वारा प्रतिबिम्बित औसत अतिशेष घट सकता है। अगली समीक्षा के समय, जब टीपीटी व्यापक प्रस्ताव दाखिल करेगा, लागत विवरणियों का व्यापक विश्लेषण किया जाएगा।

4.3 यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि किसी भी उपयोगकर्ता ने टीपीटी के दरमान में निर्धारित वर्तमान प्रशुल्क पर, शट-आउट कार्गो पर प्रभार्य प्रभारों के बारे में मैसर्स विन्सीवास एजेन्सी से प्राप्त संदर्भ के सिवाय जिसे सचिव (पोत परिवहन) के आदेश द्वारा अलग से निपटा दिया गया था, कोई आपत्ति नहीं उठाई गई है। दरमान में विसंगति दूर करने के लिए शट-आउट कार्गो हेतु प्रावधान के बारे में टीपीटी ने दरमान में सुधार के लिए एक अलग प्रस्ताव दाखिल किया है। यह प्रकरण परामर्श अवस्था में है और इस बारे में अन्तिम निर्णय, जब और जैसे ही प्राधिकरण द्वारा इसे पारित किया जाता है, लागू हो जाएगा।

4.4 टीपीटी का अनुरोध इस दरमान की वैधता सितम्बर, 2005 तक बढ़ाने के लिए है। चूंकि टीपीटी द्वारा मांगा गया विस्तार अब से केवल 6 माह के लिए है, यह प्रधिकरण इससे पहले अनुमोदित दरों को 30 सितम्बर, 2005 तक वैधता प्रदान करता है। जैसाकि टीपीटी ने सहमति व्यक्त की है, पत्तन को सलाह दी जाती है कि वह अपना प्रस्ताव अधिक से अधिक 30 जून, 2005 तक दाखिल कर दे ताकि दरमान की अगली सामान्य समीक्षा की जा सके। यदि लागत विवरणियां निर्दिष्ट समय में प्राप्त नहीं हो पाती हैं, यह प्राधिकरण उपलब्ध सूचना के आधार पर प्रशुल्क की एक पक्षीय समीक्षा कर देगा।

5. परिणामस्वरूप और ऊपर दिए गए कारणों से, और समग्र विचार-विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण अपने पिछले आदेश संख्या टीएएमपी/31/2002, दिनांक 20 सितम्बर, 2002 के माध्यम से अनुमोदित और बाद में परिवर्तित, वर्तमान दरमान की वैधता को 30 सितम्बर, 2005 तक विस्तार प्रदान करता है। टीपीटी को निदेश दिया जाता है कि वह अगली समीक्षा के लिए अपना व्यापक प्रस्ताव अधिकतम 30 जून, 2005 तक दाखिल कर दें।

अ. ल. बोंगिरवार, अध्यक्ष

[विज्ञापन/III/IV/143/04/असा.]

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS****NOTIFICATION**

Mumbai, the 28th March, 2005

**No. TAMP/26/2003-TPT.**—In exercise of the powers conferred by Sections 48, 49 and 50 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby approves the proposal received from the Tuticorin Port Trust for extension of the validity of its existing Scale of Rates as in the Order appended hereto.

**TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS**

Case No. TAMP/26/2003-TPT

Tuticorin Port Trust (TPT)

Applicant

**ORDER**

(Passed on this 15th March, 2005)

This Authority had passed an Order on 20 September 2002 approving the general revision of Scale of Rates (SOR) of the Tuticorin Port Trust (TPT). The Order along with the revised SOR was notified in the Gazette of India on 4 October, 2002 *vide* Gazette No. 224.

1.2 In the said Order, in view of the surplus position, reflected by the cost statements, this Authority had rejected the upward revision of rates proposed by the TPT except for those items specifically approved and had advised the TPT to come up with a suitable proposal in consultation with its users for reduction in tariff.

2.1 In compliance of this Authority's Order, the TPT had filed revised cost statements for the years 2002-03 and 2003-04 earlier, indicating an average deficit of 5.31% and pointed out that there was no case for downward revision; instead there was scope to revise the tariff upwards. Nevertheless, the TPT requested this Authority to continue the tariff at the rates approved in its earlier order to keep it competitive in comparison to the tariff at other Indian ports.

2.2 The cost statement filed by the TPT in December 2003, were scrutinized to eliminate various inconsistency observed therein with reference to the cost statements attached to this Authority's Order dated 20 September, 2002. The cost statement modified by us depicted net surplus position almost at the same level as was found at the time of the last general revision. Nevertheless, since the next general revision was due in September, 2004, this Authority accepted the request of the TPT to extend the then existing tariff level for one year i.e. till September, 2004 with a direction to submit its comprehensive proposal for general review by 30 June, 2004. The TPT was also advised to exercise the flexibility already given to it and to reduce the cargo and vessel related charges to extent of net surplus reflected in the cost statements.

3.1 With reference to the decision of this Authority, the TPT has submitted cost statements based on Actual 2003-04 and the Revised Estimates for the year 2004-05. The cost statements filed by the TPT show an average deficit of 5.16% for the years 2003-04 and 2004-05.

3.2 The TPT has stated that despite increase in the tariff from 130.17 lakh tonnes in the year 2001-02 to 141.99 lakh tonnes in the year 2004-05, it could not generate sufficient resources to meet the rising expenditure in capital projects, to meet the outstanding Japanese loan and other capital expenditure proposal for optimization of inner harbour, upgradation of electrical system, etc. Various incentive schemes/rebates have been introduced in the wharfage rates and other tariff items in the wake of competition from neighbouring ports which is likely to reduce the operating income. Further, 65% concession has been offered in the vessel related charges in case of main line container vessels in pursuance of the direction from the (then) Ministry of Shipping. This is likely to reduce the operating income by Rs. 5.17 crores approximately per annum.

3.3 In this backdrop, and also in view of the deficit position reflected by the cost statement, the TPT has requested to extend the validity of its current SOR till 30 September, 2005. The TPT has agreed to submit its proposal for next general review by 30 June, 2005.

4.1 The cost statement furnished by the TPT has been examined in the line with the approach followed at the time of the last general revision of the Scale of Rates of the TPT and also with reference to the general principle uniformly followed by this Authority in tariff revision/review process of other major ports and also. Some of the inconsistencies observed therein have been modified.

4.2 The modified cost statement for the port as a whole prepared by us shows average net surplus of 6.77% of the operating income for the years 2003-04 and 2004-05 as against the average net deficit of 5.16% reported by the TPT. The average surplus reflected by the cost statement may reduce if the income estimates are updated for the various concessions offered in its tariff. A detailed analysis of the cost statements will be made at the time of the next review when the TPT files a comprehensive proposal.

4.3 It may be relevant to mention that none of the users have raised any objection on the existing tariff prescribed in the Scale of Rates of the TPT except for reference received from M/s. Vicnivaas Agency about charges leviable on shut out cargo which was disposed of separately by an Order of the Secretary (Shipping). The TPT has filed a separate proposal for amendments in its SOR as regards the provisions for shut out cargo in order to remove ambiguity in the SOR. This case is under consultative stage and final decision in this regard will be applicable as and when the Order is passed by this Authority.

4.4 The request of the TPT is to extend the validity of its SOR upto September 2005. Since the extension sought by the TPT is only for six months from now, this Authority extends the validity of the rates approved earlier till September 2005. As agreed by the TPT, the port is advised to file its proposal latest by 30 June 2005 to enable the next general review its SOR. In case the cost statements are not received within the specified time, this Authority will initiate a *suo motu* review of its tariff based on the available information.

5. In the result and for reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority extends the validity of the existing Scale of Rates approved *vide* its earlier Order number TAMP/31/2002 dated 20 September, 2002, as amended subsequently, till 30 September, 2005. The TPT is directed to file its comprehensive proposal for next review by 30 June, 2005 latest.

A. L. BONGIRWAR, Chairman

[ADVT/III/IV/143/04/Exty.]